



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

No. 281]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

विषय : ब्राजील, चीन और जर्मनी से नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/23/2018-डीजीटीआर.—मै. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें ब्राजील, चीन और जर्मनी (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें तीन तत्व होते हैं अर्थात् मालीडेनम, टंगस्टन और वेनेडियन जिनमें से टंगस्टन और मालीडेनम का यौगिक 4% - 11.5% के बीच और वेनेडियन अधिकतम 3.5 प्रतिशत हो। कार्बन 0.7% - 1.3% के बीच और क्रोमियम 3.5% - 4.6% के बीच हो (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

1. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें तीन तत्व होते हैं अर्थात् मालीडेनम, टंगस्टन और वेनेडियन जिनमें से टंगस्टन और मालीडेनम का यौगिक 4% - 11.5% के बीच और वेनेडियन अधिकतम 3.5 प्रतिशत हो, है। कार्बन 0.7% - 1.3% के बीच और क्रोमियम 3.5% - 4.6% के बीच हो।

2. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग हाई स्पीड स्टील कटिंग औजारों में होता है। संबद्ध उत्पादों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 72 'लोहा और इस्पात' के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। आठ अंकीय स्तर पर वर्गीकरण अधिकांशतः 72281010 और 72281090 के अधीन है। तथापि वस्तुएं 7228 के अन्य शीर्ष के अधीन भी आ रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद का वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

3. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन उन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह आवेदन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मै. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार वे भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं और भारत में कुल उत्पादन के 83 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा या उसके किसी संबंधित पक्ष द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता का भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का प्रमुख संपूर्ण हिस्सा बनता है इसलिए याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग होने की स्थिति में है और घरेलू उद्योग है।

शामिल देश

5. वर्तमान जाँच ब्राजील, चीन और जर्मनी (संबद्ध देश) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री के लिए समर्थनकारी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उसे परिकलित सामान्य मूल्य के साथ सह-संबंधित करना उचित माना है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके भारत में उत्पादन लागत के अपने संगत मानकों/ पद्धति के अनुसार परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस से प्रकाशित आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत परिकलित की है। संगत मानकों के अनुसार चीन के मामले में कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्ययों, अंतर्देशीय मालभाड़े समुद्री बीमा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों, और वैट के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है और अपनाया गया है।

पाटन मार्जिन

8. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

9. आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हुई है और उनसे घरेलू कीमतों में कमी/ह्रास हुआ है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है। अतः इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

जांच अवधि (पीओआई)

10. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 (12 माह) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016 – मार्च, 2017 और जाँच अवधि के आकड़े शामिल होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

11. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग से नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग

से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

12. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

14. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। दी गई सूचना मूल प्रति और साफ्ट प्रति दोनों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उनसे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को यदि उनके हिस्से के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है, दो अलग-अलग सेट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

16. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां दो (2) सेट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

17. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

21. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of High Speed Steel of Non Cobalt Grade from Brazil, China and Germany

F. No. 6/23/2018-DGTR: M/s Graphite India Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of " High Speed Steel of Non Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%" (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from Brazil, China and Germany (hereinafter also referred to as the subject countries).

Product under consideration

1. The product under consideration for the purpose of present investigation is "High Speed Steel of Non Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%".
2. The subject good is used for making High Speed Steel Cutting Tools. The subject products are classified under Chapter Heading 72 "Iron and Steel" of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is majorly under 72281010 and 72281090. However, goods are coming under other heads of 7228 also. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

Like Article

3. The petitioner has submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being

treated as 'Like Article' within the meaning of the Rule 2 (d) to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

4. The Application has been filed by M/s Graphite India Limited., as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the major producers of the subject goods in India accounting for 83% of the total production in India. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries. Since the petitioner account for entire the major proportion of the total production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b).

Country involved

5. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Brazil, China and Germany (subject countries).

Normal Value

6. The applicant has claimed the normal value based on price prevailing in the subject countries. The Authority after considering the supporting evidences for the domestic sales has considered it appropriate to correlate the same with constructed normal value which have been constructed as per its consistent norms / methodology of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

Export Price

7. The applicant has computed the export price on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, credit cost and bank charges and VAT in case of China as per the consistent norms adopted.

Dumping Margin

8. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

9. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices and have suppressed/depressed the domestic prices which have led to financial losses and negative return on capital employed. Therefore, there is prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation (POI)

10. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st April 2017 to 31st March 2018 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e. April 2014 to March-2015, April 2015 to March 2016, April 2016 to March-2017 and POI.

Submission of Information

11. The exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce, Jeevan Tara Building,
4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001**

12. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
14. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

15. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.
16. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
17. The confidential version shall contain all information, which is by nature confidential and/or other information, which the supplier of such information claims, as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not

susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
21. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

22. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information or evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Designated Authority